दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

दिसंबर 2021

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **5**

- बागपत में मिले पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दुर्लभ सिक्के 5
- गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के फेज-1 का अप्रूवल मिला 5
- सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास 6
- इंटरनेशनल आर्बिटेशन सेंटर 6
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 6
- गोरखपुर में दूरदर्शन भू-उपग्रह केंद्र का लोकार्पण 7
- राज्य स्तरीय पुरस्कार 7
- मंत्र (MaNTrA) ट्रैकिंग ऐप 8
- गोरखपुर में परियोजनाओं का लोकार्पण 8
- 17 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक देने वाला उत्तर प्रदेश पहला भारतीय राज्य 9

नोट :

- गोरखपुर को 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' बनाने की घोषणा 10
- हैदरपुर वेटलैंड 10
- नि:शुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ 11
- 'सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना' राष्ट्र को समर्पित 11
- श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर 12
- नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट 12
- ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल माध्यम से आयोजन 13
- 28 अनाज गोदामों, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एवं इंटरनेट बैंकिंग तथा कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं का लोकार्पण 14
- प्रधानमंत्री ने किया गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास 14
- प्रधानमंत्री ने 1.60 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के खातों में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये 15
- स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत बने उत्तराखंड के ब्रांड एंबेस्डर 15
- मुख्यमंत्री ने दिये ड्रोन निर्माण इकाई लगाने निर्देश 16
- 'वारतां विक्रमाजीत दी' की प्रस्तुति के साथ विक्रमोत्सव-21 का समापन 16
- पाँचदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का शुभारंभ 17

नोट :

- प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में अमूल परियोजना का शिलान्यास 17
- रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी 17
- मुख्यमंत्री ने किया छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट वितरण कार्य का शुभारंभ 18
- सुशासन सूचकांक, 2021 में उत्तर प्रदेश 18
- नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश 19
- प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल को दिखाई हरी झंडी 20

दृष्टि The Vision

नोट :

उत्तर प्रदेश

बागपत में मिले पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दुर्लभ सिक्के

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में बागपत जनपद के खेकड़ा के निकटवर्ती दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से सटे गाँव काठा के प्राचीन टीले में पुरातात्त्विक स्थल निरीक्षण में दिल्ली अधिपति राजा पृथ्वीराज चौहान सहित, राजा अनंगपाल देव, राजा मदनपाल, राजा चाहड़ा राजदेव के समय के 16 दुर्लभ सिक्के प्राप्त हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- इतिहासकार डॉ. अमित राय जैन का कहना है कि यह उपलब्धि बागपत एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिये नया आयाम खोलेगी, क्योंकि किसी भी वंश के शासकों के सिक्कों की श्रृंखला प्राप्त होना, वहाँ उस क्षेत्र पर उन राजाओं के आधिपत्य को सिद्ध करता है। मुद्रा शास्त्र के आधार पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिये यह खोज़ काफी महत्त्वपूर्ण है।
- ज्ञातव्य है कि बागपत जनपद में 2005 में शहजाद राय शोध संस्थान के निदेशक डॉ. अमित राय जैन के प्रस्ताव पर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने उत्खनन कार्य किया। उसके बाद सन् 2018 में सिनौली का उत्खनन का कार्य हुआ, वहाँ से प्राप्त दुर्लभ पुरावशेष तथा तांबे से निर्मित लकड़ी के युद्ध रथ भारत में प्रथम बार प्राप्त हुए। उसके उपरांत से जनपद बागपत संपूर्ण विश्व के पुरातत्त्वविद् एवं इतिहासकारों के लिये रोमांचक खोज़ एवं शोध का केंद्रबिंदु बना हुआ है।
- इस संबंध में इतिहासकार अमित राय जैन का कहना है कि यह प्राचीन टीला हज़ारों वर्षों से यह मौजूद है। यहाँ के स्थल निरीक्षण में कई बार यहाँ से कुषाण काल एवं बाद की सभ्यताओं के अवशेष, मृद्भांड इत्यादि प्राप्त होते रहे हैं। उसी श्रृंखला में फिलहाल 16 सिक्कों का प्राप्त होना सिद्ध करता है कि यहाँ कोई बड़ी मानव बस्ती उस समय रही होगी, जहाँ पर व्यापारिक लेन-देन में सिक्कों का प्रचलन था।
- सिक्कों के खोजकर्त्ता इतिहासकार डॉ. अमित राय जैन ने सिक्कों की धातु के बारे में बताया कि यह बिलन धातु के सिक्के हैं, जिसका निर्माण चांदी एवं तांबे को मिलाकर किया जाता था। चांदी क्योंकि अति दुर्लभ थी तो सिक्कों को बनाने में उसमें तांबे की मात्रा भी मिलाई जाती थी।
- यहाँ से प्राप्त सिक्कों में कुछ सिक्कों को रासायनिक विधि से साफ किया गया है, जिससे उन पर लिखे गए नामों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जा सका है।
- पृथ्वीराज चौहान (सन् 1178-1192 ई.), चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे, जिन्होंने उत्तर-भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्द्ध में अजमेर और दिल्ली पर शासन किया था।

गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के फेज-1 का अप्रूवल मिला

चर्चा में क्यों?

- 1 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज-1 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गोरखपुर में तीन बोगियों वाली लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। इसके लिये राइट्स व लखनऊ रेल मेट्रो कॉरपोरेशन ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन कर शासन को भेज दिया है।
- राज्य सरकार ने बजट में भी गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

- डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गोरखपुर महानगर में करीब 4600 करोड़ रुपए की लागत से तीन बोगियों (कार) वाली मेट्रो ट्रेन का दो रूटों में संचालन का प्रस्ताव है। पहला रूट 15.14 किमी लंबा होगा, जो श्यामनगर (बरगदवाँ के पास) से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक जाएगा। इस पर कुल 14 स्टेशन होंगे।
- दूसरा रूट गुलरिहा से शुरू होकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, असुरन चौक, धर्मशाला, गोलघर, कचहरी चौराहा होते हुए नौसढ़ तक जाएगा। जिसमें कुल 13 स्टेशन होंगे।

सहारनपुर में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 2 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर ज़िले के पुंवारका ग्राम में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे।

प्रमुख बिंदु

- माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय की स्थापना कुल 50.43 एकड़ क्षेत्रफल में की जाएगी तथा निर्माण कार्य 18 माह में पूरा कर लिया जाएगा।
- विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, छात्रावास, आवासीय भवन आदि के निर्माण हेतु प्रथम चरण में 92.04 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।
- माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में सहारनपुर मंडल के तीनों जनपद मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर एवं शामली को सम्मिलित किया गया है।
- इन तीनों जनपदों के 264 महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध किये गए हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना से सहारनपुर मंडल के छात्र-छात्राओं को निकटतम स्थान पर ही उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- इस विश्वविद्यालय से जारी डिग्री पर माँ शाकुम्भरी का चित्र होगा।
- विश्वविद्यालय में नर्सिंग, फार्मेसी, कंप्यूटर एवं विभिन्न रोज़गारपरक पाठ्यक्रम संचालित होंगे।

इंटरनेशनल आर्बिटेशन सेंटर

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल आर्बिटेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह इंटरनेशनल आर्बिटेशन सेंटर उत्तर भारत में किसी संस्थान में खुलने वाला पहला सेंटर होगा।
- इस सेंटर से क्राइम को छोड़ देश-विदेश के अन्य सभी मामलों का निस्तारण मध्यस्थता के ज़रिये किया जाएगा।
- इस सेंटर में मामलों की सुनवाई के लिये उच्च न्यायालय के 6 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मैनेजमेंट के डीन एवं संबंधित क्षेत्र के एक्सपर्ट शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति इसके संरक्षक होंगे।
- यह सेंटर सभी निवेशकों को अपने विवाद कोर्ट के बाहर जल्दी निपटाने में सहायता करेगा।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

- 3 दिसंबर, 2021 को प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में स्थापित किये जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण डॉ. राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने की घोषणा की गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा 'उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम, 2020' पारित किया गया था।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान एवं संविधान निर्माण में उनकी भूमिका तथा प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनके उल्लेखनीय योगदानों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है।
- विदित हो कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद की ही अध्यक्षता में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति भी रहें हैं।
- ध्यातव्य है कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर, 1884 को वर्तमान बिहार के सिवान ज़िले में हुआ था तथा 28 फरवरी, 1963 को उनका देहावसान हो गया था।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1962 में भारत रत्न प्रदान किया गया था।

गोरखपुर में दूरदर्शन भू-उपग्रह केंद्र का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

- 3 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जनपद गोरखपुर में दूरदर्शन भू-उपग्रह केंद्र तथा जनपद इटावा, गदानिया जनपद लखीमपुर खीरी एवं नानपारा जनपद बहराइच में 10 किलोवॉट एफ.एम रिले केंद्र का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस भू-उपग्रह केंद्र के माध्यम से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बल्कि बिहार का एक बड़ा भाग और नेपाल की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी।
- साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहाँ थोड़ी-बहुत राष्ट्रविरोधी हलचलें होती हैं और देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों द्वारा दुष्प्रचार किया जाता है, उसे रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा।
- गोरखपुर दूरदर्शन भू-उपग्रह केंद्र पर भोजपुरी भाषा में प्रसारण होगा जिससे भोजपुरी रंगकर्मियों को एक मंच मिलेगा।
- जनपद इटावा के ट्रांसमीटर से 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
- जनपद लखीमपुर खीरी के गदानिया, जनपद बहराइच के नानपारा ट्रांसमीटर से क्रमशः 35 लाख और 25 लाख लोगों को एफ.एम. की सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में 3 और ट्रांसमीटर जनपद सुलतानपुर, जनपद रामपुर और जनपद महराजगंज में अगले 8 महीने के अंदर स्थापित किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- 3 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग व्यक्तियों तथा दिव्यांगजन के हितार्थ कार्य कर रही सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट अंकों के साथ उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।
- इसके पूर्व, उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया तथा दिव्यांगजन को सहायक उपकरण भी वितरित किये। यह कार्यक्रम दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा आयोजित किया गया था।

नोट :

- मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार अजय कुमार (श्रवणबाधित), नागेंद्र कुमार (अस्थिबाधित), नीतू द्विवेदी (दृष्टिबाधित) को प्रदान किया गया।
- वहीं दिव्यांगजन हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी का पुरस्कार केपेबिल्टी फाउंडेशन वाराणसी को प्रदान किया गया।
- दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार डॉ. सी. तुलसीदास (व्यावसायिक), इरफाना तारिक (गैर व्यावसायिक), दिव्यांगजन के निमित्त कार्यरत प्रेम धाम चैरिटेबल सोसाइटी, बिजनौर (समावेशी शिक्षा के निमित्त), भागीरथ सेवा संस्थान, गाजियाबाद (समग्र पुनर्वास सेवा) को प्रदान किया गया।
- प्रेरणास्रोत का पुरस्कार प्रो. मंगला कपूर (अस्थिबाधित), धीरज श्रीवास्तव (श्रवणबाधित), कु. जीया राय (मानसिक मंदित), सौरभ तिवारी (दृष्टिबाधित) को प्रदान किया गया
- सर्वश्रेष्ठ सृजनशील वयस्क दिव्यांग व्यक्ति का पुरस्कार नव कुमार अवस्थी, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार रति मिश्रा (महिला), लव वर्मा (पुरुष), दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु कार्यरत कर्मचारी का पुरस्कार शगुन सिंह को प्रदान किया गया।

मंत्र (MaNTrA) ट्रैकिंग ऐप

चर्चा में क्यों?

- 5 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 15 बीएसएल-2 प्रयोगशालाओं तथा माँ-नवजात ट्रैकिंग ऐप (मंत्र) 'MaNTrA' का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उन्होंने मातृ स्वास्थ्य एवं टीकाकरण सेवाओं में उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करने वाली एएनएम को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इनमें विभिन्न जनपदों में कार्यरत एएनएम शामिल हैं।
- इन 5000 नवीन उनकेंद्रों, 15 बीएसएल-2 प्रयोगशालाओं तथा माँ-नवजात ट्रैकिंग ऐप 'MaNTrA' के लोकार्पण से नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- यह स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों और पिछड़े जनपदों में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे।
- एक स्वास्थ्य उपकेंद्र 5,000 की आबादी को सुविधा प्रदान करने के लिये स्थापित किया जाता है। ये उपकेंद्र महत्त्वाकांक्षी एवं अन्य पिछड़े जनपदों में काफी बड़ी संख्या में स्थापित किये जा रहे हैं।
- इन 5,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों से एक वर्ष में ढाई से तीन करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
- इन उपकेंद्रों से महिलाओं और बच्चों के साथ ही, अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं घर के निकट प्राप्त हो सकेंगी। बच्चों के टीकाकरण में इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों की विशेष भूमिका होगी।
- 15 जनपदों में बीएसएल लैब के लोकार्पण के बाद प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आरटीपीसीआर जाँच सुविधा संपन्न लैब क्रियाशील हो जाएंगी, जो कि वायरस से होने वाली बीमारियों की जाँच सुविधा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रदेश में प्रतिदिन 4 लाख जाँच की क्षमता विकसित की जा चुकी है।

गोरखपुर में परियोजनाओं का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

- 7 दिसंबर, 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनपद गोरखपुर में लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से स्थापित परियोजनाओं- हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लि. गोरखपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) गोरखपुर तथा आई.सी.एम.आर.- रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर गोरखपुर का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- 8603 करोड़ से तैयार हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के गोरखपुर खाद कारखाने में सालाना लगभग 12.7 लाख टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा।
- इस कारखाने से राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया की उपलब्धता होगी। पूर्वांचल में रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे। खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेंटर को बढ़ावा मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि नेप्था आधारित पुराना गोरखपुर यूरिया प्लांट 1969 में लगा था। यह खाद कारखाना 10 जून, 1990 को बंद हो गया था। एफसीआई के बंद पड़े यूरिया प्लांट की जगह हिन्दुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड द्वारा चार गुना बड़ा ग्रीन फील्ड यूरिया प्लांट लगाया गया है।
- वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री ने गोरखपुर के इसी खाद कारखाने का शिलान्यास किया। पहले गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना यह नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना अधिक क्षमता का है।
- गोरखपुर खाद कारखाने के प्रिलिंग टावर की ऊँचाई कुतुब मीनार से दोगुने से भी अधिक है। कुतुब मीनार की ऊँचाई 72.5 मीटर है, जबकि प्रिलिंग टावर की ऊंचाई 149.5 मीटर है। विश्व में दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा मीटर एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने पाकिस्तान के दहरकी में बनया है। उसकी ऊँचाई 125 मीटर है, जबकि गोरखपुर खाद कारखाने की ऊँचाई इससे करीब 25 मीटर अधिक है।
- लगभग 1011 करोड़ रुपए से बन रहे गोरखपुर एम्स की क्षमता 100 बेड की है। इस केंद्रीय संस्थान का शिलान्यास जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री ने किया था।
- एम्स गोरखपुर तथा रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की स्थापना से दिमागी बुखार सहित अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव में मदद मिलेगी। बीआरडी मेडिकल कालेज परिसर स्थित रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर की अत्यधुनिक लैब 36 करोड़ की लागत से तैयार की गई हैं।

17 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक देने वाला उत्तर प्रदेश पहला भारतीय राज्य

चर्चा में क्यों ?

- 8 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश इतिहास रचते हुए 17 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में 16 जनवरी, 2021 से कोरोनावायरस के खिलाफ बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया था।
- अब तक, उत्तर प्रदेश ने 17.22 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक दी है और इसके बाद महाराष्ट्र ने 12.01 करोड़ वैक्सीन तथा पश्चिम बंगाल में 9.59 करोड़ वैक्सीन खुराक दी है।
- प्रतिशत के संदर्भ में, राज्य की 37 प्रतिशत से अधिक आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और 78 प्रतिशत से अधिक को कोविड वैक्सीन की एक खुराक मिली है।
- CoWIN के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने अब तक 11.63 करोड़ वैक्सीन की पहली खुराक दी है और 5.59 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी गई हैं।
- कोरोना वायरस के नए संस्करण ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार राज्य के लोगों को जल्द-से-जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण एवं 'हर घर'के साथ टीकाकरण में तेज़ी लाने के लिये एक विशेष रणनीति के तहत काम किया जा रहा है।
- गाँवों में चल रहे डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान में, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा दल मिथकों को तोड़ रहे हैं और लोगों को जल्द-से-जल्द कोविड वैक्सीन लेने के लिये प्रेरित कर रहे हैं।

नोट :

गोरखपुर को 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' बनाने की घोषणा

चर्चा में क्यों?

- 10 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' बनाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री ने यह घोषणा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 89वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की।
- तीन क्रियाशील एवं एक निर्माणाधीन विश्वविद्यालयों के माध्यम से ज्ञान नगर के रूप में विकसित गोरखपुर को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता के अनुरूप 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' की तर्ज़ पर 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' बनाया जाएगा।
- 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना और अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया की समस्याओं का समाधान करना है।
- धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वैश्विक परिदृश्य में रणनीतिक बदलाव के अनुरूप तैयार की गई है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को दुनिया का नंबर एक देश और भारत के बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाना है।

हैदरपुर वेटलैंड

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को देश का 47वाँ और उत्तर प्रदेश का 10वाँ तथा विश्व का 2463वाँ रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है, जिसकी पुष्टि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है।

प्रमुख बिंदु

- हैदरपुर वेटलैंड गंगा और सोलानी नदी के बीच मुज़फ्फरनगर-बिज़नौर की सीमा पर 6908 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है।
- हैदरपुर वेटलैंड एक मानवनिर्मित झील है, जिसका निर्माण वर्ष 1984 में हुआ था। यहाँ की जैवविविधता पक्षियों को आकर्षित करती है। विदेशी पक्षी मंगोलिया की पहाड़ियों को पार करते हुए यहाँ पहुँचते हैं।
- साथ ही डाल्फिन, कछुए, घड़ियाल, मगरमच्छ, तितलियों और हिरन आदि की यहाँ अनेक प्रजातियाँ विद्यमान हैं। यहाँ 30 से अधिक पेड़-पौधे की प्रजातियाँ हैं और 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, साथ ही 40 से ज़्यादा मछली प्रजातियाँ हैं और 102 से ज़्यादा जलपक्षी प्रजातियाँ हैं।
- यहाँ शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तथा अब रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर संरक्षण के नियम और तौर -तरीके बदले जाएंगे।
- गौरतलब है कि वर्ष 2018 में पहली बार यह क्षेत्र वन अफसरों की नज़र में आया था। दो साल पहले ही इसे रामसर साइट घोषित करने के लिये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल रामसर कमेटी में इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार रामसर कमेटी में शामिल तमाम देशों ने हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने पर मुहर लगा दी।
- उल्लेखनीय है कि ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी, 1971 को एक सम्मेलन हुआ था। इसमें शामिल देशों में वेटलैंड के संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ और यह 21 दिसंबर, 1975 से प्रभाव में आ गया।
- रामसर समझौते के अनुसार, वेटलैंड ऐसा स्थान है, जहाँ वर्ष में कम-से-कम आठ माह पानी भरा रहता है और 200 से ज़्यादा प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी रहती है।

नि:शुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 12 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नि:शुल्क राशन वितरण महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 लाभार्थियों को नि:शुल्क राशन वितरित किया।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि इस महाअभियान के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 80,000 राशन की दुकानों के माध्यम से दिसंबर, 2021 से मार्च, 2022 तक नि:शुल्क राशन वितरित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो योजना लागू की जा रही है, उसमें प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारक को नि:शुल्क अनुमन्य खाद्यान्न के साथ ही 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो दाल व 1 किलो चीनी उपलब्ध कराई जा रही है।
- इसी प्रकार प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्डधारक को अनुमन्य खाद्यान्न के साथ ही नि:शुल्क 1 लीटर खाद्य तेल, 1 किलो नमक तथा 1 किलो दाल उपलब्ध कराई जा रही है।
- गौरतलब है कि वर्ष 2020 में माह अप्रैल से नवंबर तक 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ ज़रूरतमंदों सहित देश के 80 करोड़ पात्र लोग लाभान्वित हुए थे। वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने भी अप्रैल से जून तक तीन माह नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया था, जिससे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों का लाभ प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी मई, 2021 (रामनवमी) से दीपावली (7 माह) तक केंद्र सरकार ने नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की योजना लागू की थी। इसी तरह प्रदेश सरकार ने भी अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जून, जुलाई तथा अगस्त, 2021 तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किया।
- प्रत्येक ज़रूरतमंद को राशन प्राप्त हो, इस दृष्टि से इस वृहद् खाद्यान्न वितरण योजना का पुन: शुभारंभ कर दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

'सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना' राष्ट्र को समर्पित

चर्चा में क्यों ?

- 11 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में 9800 करोड़ रुपए की लागत की 'सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना' को राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का काम चार दशक पहले वर्ष 1978 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बहराइच ज़िले में शुरू हुआ था, तब इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। वर्ष 1982 में बलरामपुर सहित 9 ज़िलों को इस परियोजना से जोड़ा गया।
- इस परियोजना की लंबाई 318 किमी. है, जबकि 6623 किमी. लंबी नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया है, जो इस परियोजना से लिंक हैं। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था।
- इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर तथा महराजगंज के 6,227 ग्रामों के 30 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे तथा इन 9 जनपदों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने 'नदी जोड़ो परियोजना' को पूरा करती है। यह परियोजना घाघरा नदी को सरयू नदी से, सरयू नदी को राप्ती नदी से, राप्ती नदी को बाणगंगा नदी से एवं बाणगंगा नदी को रोहिन नदी से क्रमश: जोड़ती है।

नोट :

- इस परियोजना से इस क्षेत्र के किसान सब्जी एवं बागवानी जैसे अन्य कृषिगत कार्य कर पाएंगे। कृषि उत्पादन में वृद्धि के कारण किसानों की आमदनी में इजाफा होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में घाघरा एवं सरयू नदी जहाँ मिलती हैं, वहां पर पहला बैराज बनाया गया है। यह बैराज नेपाल की सीमा से मात्र 7 किलो मीटर की दूरी पर है। इस परियोजना से यह क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से भरपूर होगा। यहाँ पर पर्यटन की अनेक संभावनाएँ विकसित होंगी। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, नौजवानों को रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे, जिससे यहाँ का नौजवान सक्षम एवं सामर्थ्यवान बनेगा।
- उल्लेखनीय है कि किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिये देश में लगभग 100 सिंचाई परियोजनाओं को लक्षित किया गया और इन सिंचाई परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ। इस योजना में प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं का चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएँ पूरी हो गई हैं। इन 17 सिंचाई परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है।

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर

चर्चा में क्यों ?

- 13 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में शिलापट्ट का अनावरण कर नव्य एवं भव्य श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। यह कॉरिडोर वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा घाट से जोड़ता है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में योगदान करने वाले श्रमसाधकों पर पुष्पवर्षा कर उन्हें सम्मानित किया तथा कार्यक्रम के उपरांत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के साथ भोजन भी किया।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का नया परिसर एक भव्य भवन मात्र नहीं है। यह भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक आत्मा, प्राचीनता, परंपराओं, भारत की ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है।
- यह मंदिर कॉरिडोर पहले केवल 3 हज़ार वर्गफीट में था, जो अब लगभग 5 लाख वर्गफीट का हो गया है। अब यहाँ मंदिर परिसर में 50 से 70 हज़ार श्रद्धालु आ सकेंगे।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 1777-1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में महती योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर को स्वर्णमंडित कराया था। ग्वालियर की रानी ने भी मंदिर में अपना योगदान किया था।
- गौरतलब है कि पिछले करीब एक हज़ार साल में कई बार काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई। इस मंदिर को पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194ई. में ध्वस्त किया। इस मंदिर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447ई. में किया। 1642ई. में शाहजहाँ ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया।

नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

- 15 दिसंबर, 2021 को नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ॠतु महेश्वरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि हेलीपोर्ट प्रोजेक्ट की डीपीआर, डिज़ाइन और कई दूसरी औपचारिकताओं को राज्य सरकार की ओर से पहले मंज़ूरी दी जा चुकी है। इस परियोजना पर नोएडा विकास प्रशासन पिछले 5 सालों से कार्य कर रहा है।

- इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मॉडल) पर नोएडा के सेक्टर-151ए में 9.35 एकड़ में बनाया जाएगा और इस पर 43.13 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- हेलीपोर्ट निर्माण के लिये ग्लोबल टेंडर के ज़रिये कंपनी की तलाश की जाएगी। इसका निर्माण करने वाली कंपनी को ही अगले 30 सालों के लिये इस हेलीपोर्ट का संचालन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी।
- नोएडा हेलीपोर्ट का निर्माण जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज़ पर किया जाएगा। इसके लिये ज़मीन नोएडा विकास प्राधिकरण ही उपलब्ध करवाएगा।
- नोएडा के इस हेलीपोर्ट का उपयोग बहुउद्देश्यीय होगा। यहाँ से कमर्शियल उड़ानें भी भरी जाएंगी, जिनके लिये बेल-412 हेलीकॉप्टर उपयोग होते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स में 12 यात्री सवार हो सकते हैं।
- वीवीआईपी मूवमेंट के लिये इस्तेमाल होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर एमआई-172 भी यहाँ लैंड-टेकऑफ कर सकेगा। इन हेलीकॉप्टर की क्षमता 26 यात्रियों को लाने या ले जाने की होती है। इन बड़े हेलीकॉप्टर की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नोएडा हेलीपोर्ट की डिज़ाइन तैयार की गई है।
- उल्लेखनीय है कि हेलिकॉप्टर खड़ा करने की जगह को हेलीपैड कहा जाता है और जहाँ एक या एक से अधिक हेलीपैड होते हैं, उस एरिया को हेलीपोर्ट कहते हैं।

ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल माध्यम से आयोजन

चर्चा में क्यों?

- 17 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किय गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। यह ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक थी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस नगरीय क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने की एक सुनिश्चित योजना का हिस्सा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 120 महापौर व्यवस्थित विकास के इस मॉडल को समझकर और अपने अनुभवों को इस कॉन्फ्रेंस में साझा करते हुए विकास के सस्टेनेबल मॉडल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि शहर अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति हैं। शहरों को वाइब्रेंट इकोनॉमी का हब बनाना चाहिये। एक समग्र प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जहाँ एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये सभी सुविधाएँ एक साथ विकसित हों तथा जो आर्थिक गतिविधियों को आमंत्रित करने के साथ ही उन्हें बढ़ावा भी दें।
- प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 'एक जनपद एक उत्पाद' स्वरोज़गार को विकसित करने की एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इस योजना द्वारा ज़िले की परंपरागत कला, हस्तशिल्प, उद्यम कला को विशिष्ट पहचान और उसे उद्यम गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
- उन्होंने महापौरों से कहा कि वे अपने शहर के किसी विशिष्ट उत्पाद अथवा स्थान की विशिष्ट पहचान को विकसित करें। उन्होंने महापौरों से अपने शहर में रेहड़ी-पटरी दुकानदारों की एक सूची बनाने और उनको योजनाओं से जोड़ने तथा डिजिटल लेन-देन एवं वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के निर्देश दिये।
- प्रधानमंत्री ने महापौरों से कहा कि 'सुगम्य भारत अभियान-सुलभ भारत अभियान' के तहत शहरों में दिव्यांगों के अनुकूल सुविधाओं को विकसित किया जाए।

28 अनाज गोदामों, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एवं इंटरनेट बैंकिंग तथा कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 17 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा निर्मित 28 अनाज गोदामों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय पर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एवं इंटरनेट बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं का लोकार्पण तथा नाबार्ड से वित्त पोषित 294 पैक्स में कम्प्यूटराइज़ेशन कार्य का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय भवन तथा ए.सी.एस.टी.आई. के मीटिंग हॉल एवं 32 कक्षों के हॉस्टल के जीर्णोद्धार कार्यों का भी उद्घाटन किया।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा 28 नए गोदाम बनाए हैं। यहाँ लगभग डेढ़ लाख मीट्रिक टन अनाज की वैज्ञानिक तरीके से भंडारण की व्यवस्था होगी। इसके तहत पीलीभीत, मिर्ज़ापुर, बस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, अमरोहा, बिज़नौर, रामपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, बदायूँ, बरेली, महराजगंज, भदोही, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कौशांबी और फतेहपुर में भंडार गृह बनाए गए हैं।
- उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाओं- फतेहपुर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा, संभल, अमेठी, अंबेडकरनगर, गोरखपुर तथा महराजगंज का उद्घाटन किया गया है। साथ ही मुख्यालय का लोकार्पण भी किया गया है।
- कृषि प्रशिक्षण संस्थान हब तथा नाबार्ड के वित्तपोषण से प्रदेश के लगभग 300 पैक्स में कंप्यूटराइज़ेशन का कार्य हुआ है। पैक्स में कम्प्यूटराइज़ेशन से भ्रष्टाचार की संभावनाएँ समाप्त हो जाएंगी। पैक्स को ज़िला कोऑपरेटिव बैंक से, ज़िला कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड से जोड़ा जाएगा।
- उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने लगभग 46,000 से अधिक कोऑपरेटिव्स- गन्ना, मत्स्य, रेशम, खादी ग्रामोद्योग, हैण्डलूम, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हाउसिंग या पैक्स सभी में पारदर्शिता लाने के लिये बहुत बड़ा अभियान संचालित किया है। इससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
- ज्ञातव्य है कि 19 प्रतिशत एग्रीकल्चर फाइनेंस, उर्वरक वितरण लगभग 35 प्रतिशत सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जाता है। 25 प्रतिशत खाद का उत्पादन सहकारिता समितियों द्वारा किया जाता है। लगभग 22 प्रतिशत दूध की खरीद एवं उत्पादन सहकारिता के माध्यम से होता है। गेहूँ की 22 प्रतिशत खरीद, 20 प्रतिशत धान की खरीद तथा 21 प्रतिशत मत्स्य संबंधी कार्य सहकारिता के माध्यम से किये जाते हैं।
- लगभग 8 लाख 55 हज़ार सहकारी समितियाँ देश भर में अनेक क्षेत्रों में फैली हैं। यह समितियाँ छोटे-छोटे लोगों को जोड़कर बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। लिज्जत पापड़, अमूल दूध, इफ्को व कृभको खाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती हैं।

प्रधानमंत्री ने किया गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 18 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना की आधारशिला रखी। गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज तक 12 ज़िलों से होकर गुज़रेगा तथा यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे होगा।

प्रमुख बिंदु

- 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ेगा। यह मेरठ ज़िले के बिजौली गाँव के पास (NH-334) से शुरू होकर प्रयागराज ज़िले के जुदापर डांडू गाँव (NH-19) के पास खत्म होगा।
- इसके बनने के बाद दिल्ली से प्रयागराज के बीच यात्रा में लगने वाला 10-11 घंटे का समय कम होकर 6-7 घंटे रह जाएगा।

नोट :

- गंगा एक्सप्रेस-वे को भविष्य में 8 लेन का किये जाने और ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 1047 किमी. लंबा किये जाने की योजना है।
- गंगा एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बन जाएगा। वर्तमान में देश और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (341 किलोमीटर) है जिसका नवंबर 2021 में उद्घाटन हुआ था।
- गंगा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के 12 ज़िलों- मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूँ, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुज़रेगा तथा इन 12 ज़िलों के 500 से अधिक गाँवों को भी जोड़ेगा।
- गंगा एक्सप्रेस-वे की अनुमानित लागत 36,230 करोड़ रुपए है, जिसमें जमीन अधिग्रहण पर करीब 9500 करोड़ रुपए का खर्च भी शामिल है। इसका निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज और IRB इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपर्स करेंगे।
- इस एक्सप्रेस-वे में सात ओवरब्रिज, 17 इंटरचेंज रोड, 14 बड़े पुल, 126 छोटे पुल, 28 फ्लाईओवर, 50 वाहन अंडरपास और 946 पुलिया होंगी।
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की तरह ही गंगा एक्सप्रेस-वे में भी आपातकालीन स्थिति में एयरफोर्स के विमानों की लैंडिंग के लिये शाहजहाँपुर के पास एक 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस-वे पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की आपात्कालीन लैंडिंग के लिये एयर स्ट्रिप के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जिसके चार एक्सप्रेस-वे पर ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पहले ही यमुना एक्सप्रेस-वे पर मथुरा के पास एक एयर स्ट्रिप मौजूद है। इसके अलावा लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर बाँगरमऊ के पास भी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। हाल ही में शुरू हुए 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे में भी एयरफोर्स के विमानों की आपात् लैंडिंग के लिये सुल्तानपुर के पास 3 किलोमीटर से अधिक लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है।

प्रधानमंत्री ने 1.60 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के खातों में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये

चर्चा में क्यों?

- 22 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संगम के पास परेड ग्राउंड में स्वयं सहायता समूहों की दो लाख से अधिक महिला प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए 1.60 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के खातों में 1,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये।

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में इस 'मातृ शक्ति महाकुंभ' में 43 जिलों के 202 'टेक होम राशन प्लांट' की नींव भी रखी। साथ ही उन्होंने 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के 1.01 लाख नए लाभार्थियों के खातों में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये।
- नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीसी सिऽयों के माध्यम से अब तक 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन किया जा चुका है।
- विभिन्न ब्लॉकों में 'पुश्तहार संयंत्र परियोजना' पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इससे महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ-साथ स्थानीय किसानों को भी लाभ होगा, जो उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना से 16 लाख से अधिक महिलाएँ सीधे लाभान्वित होंगी और जरूरतमंदों को पौटिष्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत बने उत्तराखंड के ब्रांड एंबेस्डर

चर्चा में क्यों?

- 20 दिसंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को राज्य में खेल को बढ़ावा देने और राज्य के युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 'राज्य ब्रांड एंबेस्डर' नियुक्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- धामी ने ट्विटर पर राज्य के युवाओं को खेल और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पंत को 'राज्य ब्रांड एंबेस्डर' नियुक्त करने की खबर साझा की। धामी ने युवा क्रिकेटर को एक वीडियो कॉल किया और उन्हें एक बैठक के लिये आमंत्रित किया।

नोट :

- ऋषभ राजेंद्र पंत एक भारतीय क्रिकेटर हैं, जो इंडियन प्रीमियर लीग में भारत, दिल्ली और दिल्ली कैपिटल्स के लिये मध्य क्रम के विकेटकीपर बल्लेबाज़ के रूप में खेलते हैं। दिसंबर 2015 में उन्हें 2016 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिये भारत की टीम में नामित किया गया था।

मुख्यमंत्री ने दिये ड्रोन निर्माण इकाई लगाने निर्देश

चर्चा में क्यों ?

- 22 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा राहत, कृषि और कानून व्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों में मानव रहित विमानों के महत्त्व को देखते हुए अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाई स्थापित करने के लिये एक ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को ड्रोन के उपयोग पर नियमों और विनियमों को चार्ट करने तथा राज्य के गाँवों एवं शहरों के समृद्ध इतिहास को संकलित करने की योजना बनाने के भी निर्देश दिये।
- उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्रोन तकनीक पर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा, जिसके लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से आवश्यक मदद ली जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य भर के शहरों और ग्राम पंचायतों के समृद्ध पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का दस्तावेज़ीकरण करने के लिये इस संबंध में आँकड़ों के संकलन करने और शहरी एवं ग्रामीण विकास विभागों को उत्तर प्रदेश दिवस की तर्ज़ पर क्रमशः 'ग्राम दिवस' और 'नगर दिवस' मनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिये।

'वारतां विक्रमाजीत दी' की प्रस्तुति के साथ विक्रमोत्सव-21 का समापन

चर्चा में क्यों ?

- 22 दिसंबर, 2021 को 'वारतां विक्रमाजीत दी' की प्रस्तुति के साथ महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ का प्रतिष्ठा आयोजन तीन दिवसीय विक्रमोत्सव-2021 का औपचारिक समापन हुआ। विक्रमोत्सव-2021 में भारी ठंड के बीच भी तीनों दिन नाट्य प्रस्तुति को देखने के लिये बड़ी संख्या में कलारसिकों की भागीदारी दिखी।

प्रमुख बिंदु

- विक्रमोत्सव-2021 के प्रथम दिन महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' की प्रस्तुति रंग निर्देशक संजीव मालवीय के निर्देशन में हुई। यह महानाट्य कभी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हुआ था, जिसे निर्देशक मालवीय द्वारा पारंपरिक और थ्रीडी सिस्टम में समेट कर करीब दो घंटे की अवधि में प्रस्तुत किया गया।
- इसी कड़ी में दूसरी प्रस्तुति मालवा की माच शैली में खेल माच का 'राजा विक्रम' की प्रस्तुति पंडित ओमप्रकाश शर्मा के निर्देशन में हुई।
- विक्रमोत्सव-2021 की तीसरी और अंतिम प्रस्तुति 'वारतां विक्रमाजीत दी' थी। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक राजीव सिंह की इस प्रस्तुति में पंजाबी लोकगीतों में विक्रमादित्य को खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के माध्यम से यह बात भी स्थापित हो जाती है कि विक्रमादित्य की कीर्ति केवल मालवांचल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर राज्य में है।
- महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि विक्रमोत्सव अब देश के प्रमुख शहरों-अयोध्या, पटना, बनारस, आगरा, मथुरा, चंडीगढ़, पुणे, जयपुर, दिल्ली एवं बंगलूरू में आयोजित किया जाएगा। साथ ही 'भारत विक्रम' शीर्षक से भारत उत्कर्ष एवं नव-जागरण पर केंद्रित व्याख्यान माला देश के प्रमुख शहरों में भी आयोजित किये जाने की योजना है।
- उन्होंने कहा कि विक्रमोत्सव देश के अन्य शहरों में किये जाने का उद्देश्य विक्रम कीर्ति से समाज को परिचित कराना है। विक्रम कीर्ति सार्वभौमिक रही है और यही बात समाज तक पहुँचानी है।

पाँचदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 22 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित होने वाले पाँचदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 26 दिसंबर, 2021 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है। मेले की थीम 'लघु वनोपज से स्वास्थ्य सुरक्षा' है।
- इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य वनोपज उत्पाद से जुड़े हितग्राहियों को बेहतर बाज़ार और वनोपज का अधिक-से-अधिक मूल्य दिलवाना है। इसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के विषय विशेषज्ञ आभासी तरीके से भाग लेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय मेले में वन विभाग की योजनाओं पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले में दुर्लभ किस्म की जड़ी-बूटियाँ और वन समितियों एवं वन-धन केंद्रों द्वारा तैयार किये गए उत्पाद आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मेले में अकाष्ठीय वनोपज, औषधीय पौधों, वनोपज से जुड़े संग्राहकों, व्यापारियों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों और नीति-निर्धारकों को मंच उपलब्ध कराया जाएगा। वनों से महुआ, अचार, गुठली, चिरौंजी, शहद, जड़ी-बूटी आदि संचित करने वाले वनवासियों को शासन की सहायता से एक अच्छा बाज़ार और व्यापार का अवसर मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में अमूल परियोजना का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

- 23 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली अमूल की बनास-काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया।

प्रमुख बिंदु

- डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री ने प्रमाणन चिह्न, डेयरी मार्क भी लॉन्च किया तथा डिजिटल माध्यम से बनास डेयरी से जुड़े 1,70,000 किसानों के खातों में 35 करोड़ रुपए की बोनस धनराशि अंतरित की।
- इस अवसर पर श्वेत क्रांति पर आधारित एक वृत्तचित्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रदेश में चल रही परियोजना और संकल्पना का खाका खींचा गया है।
- प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 6 नए भू-स्वामियों को अपने कर-कमलों से घरौनी प्रदान करने के साथ ही राज्य के 20 लाख परिवारों को घरौनी वितरित की।
- प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कुल 2095 करोड़ रुपए की कुल 27 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने रामनगर में देश का सबसे बड़ा गोबर बायोगैस प्लांट का भी शुभारंभ किया गया।
- विदित हो कि भारत दुनिया का लगभग 22 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन करता है। वहीं उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है।

रक्षा मंत्री ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों ?

- 26 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और डीआरडीओ की रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ब्रह्मोस भारतीय सेना के लिये अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक मिसाइल विकसित करने हेतु भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा एनपीओएम, रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- ब्रह्मोस परियोजना से 5,500 नए रोज़गार के अवसर पैदा होने का अनुमान है, जबकि सहायक आपूर्ति श्रृंखला अतिरिक्त 10,000 रोजगार पैदा करेगी।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय रक्षा बलों के तीनों अंगों-थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने पहले ही ब्रह्मोस उन्नत हथियार प्रणाली को शामिल कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने किया छात्रों को स्मार्टफोन, टैबलेट वितरण कार्य का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 25 दिसंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने की एक अन्य पहल में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण कार्य का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में अंतिम वर्ष के छात्रों को एक लाख स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किये।
- इस कार्यक्रम में राज्य के हर ज़िले से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इन स्मार्टफोन और टैबलेट के ज़रिये उन्हें न सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट मिलेगा, बल्कि रोज़गार से जुड़ी जानकारियाँ भी मिलेंगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के एक करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिये उन्हें मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिये जाएंगे। इसी के तहत उन्होंने पहले चरण में युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बाँटे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'डिजी शक्ति पोर्टल' और 'डिजी शक्ति अध्ययन ऐप' का भी शुभारंभ किया। डिजी शक्ति अध्ययन ऐप सभी स्मार्टफोन और टैबलेट पर इंस्टॉल किया गया है।
- डिजी शक्ति अध्ययन ऐप के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय या विभाग छात्रों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही बूट लोगो और वॉलपेपर के माध्यम से सरकार की ओर से रोज़गार संबंधी योजनाओं और ऐसी ही अन्य युवा कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
- विशेष सचिव (आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स) कुमार विनीत ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिये विस्तृत योजनाएँ बनाई हैं। स्मार्टफोन और टैबलेट के माध्यम से युवाओं को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोज़गार के लिये उत्कृष्ट सामग्री प्रदान की जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
- उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले राज्य के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिये जाएंगे। इसके बाद कार्यक्रमों का आयोजन कर ज़िलों में स्थानीय स्तर पर स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण किया जाएगा।

सुशासन सूचकांक, 2021 में उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों?

- 25 दिसंबर, 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप 'बी' में उत्तर प्रदेश को 5वीं रैंक प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- जीजीआई-2021 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों- समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में बाँटकर रैंकिंग दी गई है। जीजीआई-2021 तैयार करने के लिये 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है।
- उत्तर प्रदेश ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.628 स्कोर के साथ ग्रुप 'बी'में 5वीं रैंक प्राप्त की है, वहीं मध्य प्रदेश को ग्रुप 'बी'में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तथा गुजरात ने ग्रुप 'ए'में प्रथम रैंक प्राप्त की है।
- उत्तर प्रदेश ने पिछले सूचकांक (2019) की तुलना में अपने स्कोर में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.25 था, जो अब बढ़कर 4.63 हो गया है।
- उत्तर प्रदेश ने मूलत: समाज कल्याण एवं विकास तथा न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र में सुधार किया है।
- सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग तथा स्कोर निम्नलिखित हैं-

क्षेत्र	उत्तर प्रदेश की रैंकिंग	स्कोर
1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र	7वीं	0.435
2. वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र	प्रथम	0.680
3. मानव संसाधन विकास क्षेत्र	द्वितीय	0.568
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	8वीं	0.167
5. सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र	7वीं	0.537
6. आर्थिक शासन क्षेत्र	7वीं	0.337
7. समाज कल्याण एवं विकास	7वीं	0.448
8. न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा	तृतीय	0.322
9. पर्यावरण क्षेत्र	चतुर्थ	0.333
10. नागरिक केंद्रित शासन	द्वितीय	0.802

नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

- 27 दिसंबर, 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिये अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है, वहीं केरल शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट को तीन भागों में बाँटा गया था- बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिज़ोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा जबकि नागालैंड सबसे नीचे रहा।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद दादरा और नगर हवेली दूसरे नंबर पर तथा दिल्ली तीसरे नंबर पर है।
- बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश 30.57 स्कोर के साथ 19 राज्यों में अंतिम स्थान पर है, हालाँकि, आधार वर्ष (2018-19) से संदर्भ वर्ष (2019-20) में उच्चतम वृद्धिशील परिवर्तन दर्ज करके वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा।
- बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में केरल 82.20 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु 72.42 स्कोर के साथ दुसरे एवं तेलंगाना 69.96 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
- नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है, जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक हैं।

नोट :

प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल को दिखाई हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

- 28 दिसंबर, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानगर कानपुर में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के बन चुके सेक्शन का उद्घाटन किया तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ मेट्रो की सवारी की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री ने नई कानपुर मेट्रो ट्रेन से आईआईटी कानपुर से मोतीझील तक 9 किमी. लंबे खंड का निरीक्षण करने के लिये यात्रा की।
- कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32 किमी. है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है।
- कानपुर मेट्रो देश में सबसे तेज़ी से बनने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 15 नवंबर, 2019 को कानपुर मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया था और दो साल से भी कम समय में 10 नवंबर, 2021 को 9 किमी. की लंबाई वाले कानपुर IIT से मोतीझील तक के कॉरिडोर का ट्रायल रन किया गया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। इस बार दीक्षांत समारोह में सभी छात्रों को नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के तहत संस्थान के ही बनाए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से डिजिटल डिग्री दी गई। इन डिजिटल डिग्रियों को पूरे विश्व में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। इन डिग्रियों के साथ फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता।
- कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बिछाई गई बीना-पनकी बहु-उत्पाद पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। 356 किमी. लंबी इस परियोजना की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी से कानपुर नगर में पनकी तक फैली इस परियोजना से क्षेत्र में बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में मदद मिलेगी।